



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 22, 2018/अग्रहायण 1, 1940

No. 371]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 2018/AGRAHAYANA 1, 1940

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2018

**अंतिम जांच परिणाम**

**विषय – यूरोपीय संघ और संयुक्त अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेथाइलीन क्लोराइड" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा।**

**क. मामले की पृष्ठभूमि**

**फा.सं. 7/15/2018-डीजीएडी.—**1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, निर्धारण और पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

- जबकि उपर्युक्त अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने यूरोपीय संघ और संयुक्त अमरीका और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेथाइलीन क्लोराइड" के आयातों के विरुद्ध 4 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं. 14/19/2012-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच परिणाम 06 सितंबर, 2013 को अधिसूचित किए गए थे और वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं. 24/2013-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा अनंतिम शुल्क लगाए गए थे। उसके बाद प्राधिकारी ने संबंधित सामानों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश

करते हुए 2 अप्रैल, 2014 को अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे। संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामानों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21 मई, 2014 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 24/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाए गए थे।

3. जबकि अधिनियम और नियमावली के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक पूर्व में रद्द न किया गया हो, इसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा।
4. और, उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी, प्राधिकारी के लिए इस उपाय की समाप्ति से पूर्व उपयुक्त समयावधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
5. और जबकि, मै. गुजरात फ्लूरोकेमिकल्स लिमिटेड और मै. केमप्लास्ट सनमार लि. (जिन्हें यहां आगे **"याचिकाकर्ता"** अथवा **"आवेदक"** भी कहा गया है) ने यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेथाइलीन क्लोराइड (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) का पाटन जारी रहने और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों का पाटन जारी रहने की संभावना तथा परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति का आरोप लगाते हुए अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया। आवेदकों ने प्राधिकारी से समीक्षा तथा इन देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।
6. और जबकि नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन पत्र के मद्देनजर और यह पाए जाने पर कि संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) तथा यूरोपीय संघ (ई यू) (जिन्हें यहां आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए औचित्य के लिए मौजूद हैं; प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए दिनांक 3 मई 2018 की अधिसूचना सं. फा. सं. 7/15/2018-डीजीएडी द्वार सार्वजनिक सूचना जारी की कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
7. चूंकि जांच की अवधि में कोरिया गणराज्य से संबद्ध सामानों का कोई आयात नहीं हुआ था और परिणामस्वरूप कोरियाई उत्पादकों द्वारा वर्तमान पाटन का कोई साक्ष्य नहीं है अतः कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा शुरू नहीं की गई थी।
8. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में मूल जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

**ख. सामान्य प्रक्रिया**

9. प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त जांच की शुरुआत अधिसूचित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी करने के बाद इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है।
  - i. प्राधिकारी ने नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांच करने के लिए कार्यवाही करने से पूर्व पाटनरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों/मिशनो को अधिसूचित किया।
  - ii. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की इस अधिसूचना की प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों/मिशनो, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य भारतीय उत्पादकों तथा घरेलू उद्योग को भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे जांच की शुरुआत की अधिसूचना के 40 दिन के भीतर लिखित रूप में अपने ज्ञात विचार दें।
  - iii. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों/मिशनो तथा ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
  - iv. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों/मिशनो से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र तथा प्रश्नावली की प्रति भी उन्हें संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों एवं पतों सहित भेजी गई थी।
  - v. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए निर्यातक प्रश्नावली भेजी :

**यूरोपीय यूनियन**

- (क) डॉ कैमिकल्स
- (ख) इनिओस चलोरे लिमिटेड
- (ग) अकाजो नोबेल इंडस्ट्रीयल कैमिकल्स लि.
- (घ) सोल्वे एसए-रूए डे रंसबीक
- (ङ) अरकेमा एसए
- (च) मै. अकजो नोबेल इंडस्ट्रीयल कैमिकल्स बी.वी.

**संयुक्त राज्य अमरीका**

- (क) ओलिन कॉर्पोरेशन
  - (ख) ओसीडेंटल कैमिकल कॉर्पोरेशन
  - (ग) डॉ टेक्सास ऑपरेशन 2301
- vi. तथापि, किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा भेजी गई प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।
- vii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत से संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी :
- (क) वर्धमान ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
  - (ख) हर्ष कुमार एंड कंपनी
  - (ग) रालचेम लिमिटेड
  - (घ) मोरपिएन एलएबीएस
  - (ङ) सूर्या मेडिकेयर लिमिटेड
  - (च) इंडसोल ड्रग्स लिमिटेड
  - (छ) मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
  - (ज) यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड
  - (झ) केडीएल बायोटेक लिमिटेड
  - (ञ) सन फार्मास्युटीकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  - (ट) रेल्स इंडिया लिमिटेड
  - (ठ) अलेम्बिक लिमिटेड
  - (ड) हिन्दुस्तान कैमिकल्स इंडस्ट्रीज
- viii. तथापि, संबद्ध सामानों के किसी भी आयातक ने प्राधिकारी द्वारा भेजी गई प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।
- ix. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
- x. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, डीजीसीआईएंड एस से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेनदेन वार ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा के परिकलन और लेन-देनों की उचित जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- xi. यह सुनिश्चित करने के लिए क्षतिरहित (एनआईपी) कीमत निकाली गई है कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क ईष्टतम उत्पादन लागत और भारत में संबद्ध सामानों की निर्माण लागत तथा बिक्री लागत के आधार पर घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। ईष्टतम उत्पादन लागत और संबद्ध सामानों की निर्माण लागत तथा बिक्री लागत सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर है।
- xii. प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार, मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने हेतु 26 जुलाई, 2018 को मौखिक सुनवाई की। इस सुनवाई में केवल घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिन्होंने अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत किए तथा बाद में उन्हें सलाह दी गई थी कि वे प्राधिकारी को लिखित अनुरोध दायर करें।

- xiii. जांच के अनिवार्य तथ्यों को प्रकट करते हुए प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए 12 नवंबर, 2018 को जारी किया गया था। इस जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किए हैं। अतः घरेलू उद्योग के अलावा, ऐसे कोई अनुरोध नहीं हैं जिनको प्राधिकारी द्वारा हल किए जाने की आवश्यकता हो।
- xiv. आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग के आंकड़ों का सत्यापन किया गया था। केवल आवश्यक संशोधन के साथ उस सत्यापित सूचना, जहां भी लागू थी, पर प्राधिकारी द्वारा विश्वास किया गया है।
- xv. वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और जांच की अवधि शामिल है।
- xvi. गोपनीय आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, घरेलू उद्योग को निर्देश दिए गए थे कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- xvii. जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को अगोपनीय माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम रिकॉर्ड किए हैं।
- xviii. इस दस्तावेज में "\*\*\*\*" गोपनीय आधार पर प्राधिकारी को दी गई तथा नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना है।
- xix. जांच की अवधि के लिए विनिमय दर प्राधिकारी द्वारा 66.07 रूपए = 1 अमरीकी डॉलर ली गई है।

#### ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

##### ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

10. घरेलू उद्योग के विचार निम्नलिखित हैं :-

- यह जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है। मूल जांच में और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल उत्पाद मिथाइलीन क्लोराइड है, जो डिक्लोरोमिथेन अथवा मिथाइलीन डैक्लोराइड (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" अथवा "पीयूसी" अथवा "एमडीसी") के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किया गया है।
- मिथाइलीन क्लोराइड मोलक्यूलर फार्मूला  $CH_2Cl_2$  वाला आर्गेनिक सम्मिश्रण है। यह स्वाद में मीठा इथरलाइक गंध युक्त रंगहीन द्रव है और प्रमुख रूप से घोल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रयोग की अधिकतम स्थितियों में अनिवार्य रूप से गैर-ज्वलनशील होता है। तथापि, यदि तेजी से गर्म किया जाए तो जलाया जा सकता है। मिथाइलीन क्लोराइड टॉक्सिक गैस बनाते हुए उच्च तापमान पर कंपोजहीन किया जा सकता है। यह कई घोलों में पूरी तरह मिश्रणीय है।
- मिथाइलीन क्लोराइड एक घोल है और पोलिकाबोनेट तथा फिनोलिक रेजिन, रेयन यार्न फार्मास्युटीकल एगो तथा फ्रेरेंस कैमिकल्स के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग खाद्य चर्बी, कोको, मक्खन और तत्वों के लिए पृथकारी के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है।
- इस जांच में विचाराधीन उत्पाद वही होना चाहिए जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था।
- यह मानते हुए कि वर्तमान जांच मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के लिए है तथा यह कि विचाराधीन उत्पाद की पूर्व जांचों से इसमें कोई प्रमुख सुधार नहीं हैं, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रखे जाने की आवश्यकता है जो मूल जांच में था।
- संबद्ध सामानों के कोई ग्रेड नहीं हैं। तथापि, इसका व्यापार लूज अथवा पैकड रूप में किया जा सकता है जिसका कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

vii. मिथाइलीन क्लोराइड सीमाशुल्क उप शीर्ष 29031200 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 (आर्गेनिक कैमिकल) के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

viii. मिथाइलीन क्लोराइड के उत्पादन के लिए दो प्रक्रियाएं हैं : मिथेन रूट और मिथोनल रूट। दोनों माध्यमों से उत्पादित उत्पाद में अनिवार्य रूप से समान तकनीकी विशेषताएं हैं। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया में अंतर से भिन्न उत्पाद नहीं होते।

## ग.2 अन्य हितवद्ध पक्षकारों के विचार

11. चूंकि घरेलू उद्योग के अलावा किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने इस जांच में भाग नहीं लिया है, अतः प्राधिकारी के लिए विचार करने हेतु अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं है।

## ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद मिथाइलीन क्लोराइड है जिसे डिक्लोरोमिथेन अथवा मिथाइलीन क्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है। यह मोलक्यूलर फार्मूला  $CH_2Cl_2$  वाला आर्गेनिक सम्मिश्रण है। यह स्वाद में मीठा इथरलाइक गंध युक्त रंगहीन द्रव है और प्रमुख रूप से घोल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रयोग की अधिकतम स्थितियों में अनिवार्य रूप से गैर-ज्वलनशील होता है। तथापि, यदि तेजी से गर्म किया जाए तो जलाया जा सकता है। एमडीसी गैस बनाते हुए उच्च तापमान पर कंपोजहीन किया जा सकता है। यह कई घोलों में पूरी तरह मिश्रणीय है।

13. संबद्ध सामान सीमाशुल्क उप शीर्ष 29031200 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 (आर्गेनिक कैमिकल) के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह इस जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

14. वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते और प्राधिकारी द्वारा पूर्व में सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर लागू होने के नाते प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच में संबद्ध सामानों का क्षेत्र वही है, जो मूल जांच में है।

15. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नलिखित प्रावधान है:-

*“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;*

16. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में विचाराधीन उत्पाद से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं।

17. इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।

## घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

### घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

18. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

i. यह याचिका विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों के रूप में गुजरात फ्लोरोकैमिकल्स लिमिटेड और कैम्पलास्ट सनमार द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी। भारत में संबद्ध सामानों के तीन अन्य उत्पादक, यथा – टीजीवी एसआरएएसी लिमिटेड (पूर्व में श्री रायलसीमा अल्कलीज एंड एलाइड कैमिकल्स लिमिटेड), गुजरात अल्कलीज एंड कैमिकल्स लिमिटेड तथा एस आर एफ लिमिटेड हैं। इस याचिका का समर्थन टीजीवी एसआरएएसी लिमिटेड ने किया है।

ii. आवेदकों का कुल घरेलू उत्पादन में 52.80 प्रतिशत उत्पादन है और इसीलिए भारत में संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादन के प्रमुख अनुपात लेने के रूप में माना जा सकता है।

- iii. समर्थक सहित आवेदकों का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन का 69.12 प्रतिशत है।
- iv. नियम 2(ख) के अभिप्राय से जांच की अवधि के दौरान आवेदकों अथवा उनके किसी संबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं है और न ही वे संबद्ध देशों के लिए किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित हैं। अतः आवेदक स्पष्ट रूप से आधार के मानदंड को पूरा करते हैं और नियमावली के अभिप्राय से घरेलू उद्योग हैं।

## घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

19. चूंकि घरेलू उद्योग के अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस जांच में भाग नहीं लिया है, अतः प्राधिकारी के लिए विचार करने हेतु अन्य हितबद्ध पक्षकारों के कोई अनुरोध नहीं हैं।

## घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. आवेदन गुजरात फ्लोरोकैमिकल्स लिमिटेड और कैम्प्लास्ट सनमार लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है।
21. आवेदकों द्वारा अपनी याचिका के भाग के रूप में दी गई सूचना के अनुसार यह देखा जा सकता है कि आवेदकों का कुल घरेलू उत्पादन में 52.80 प्रतिशत हिस्सा है और समर्थक मै. टीजीवी एसआरएएसी लिमिटेड के उत्पादन को शामिल करने के बाद उनका कुल भारतीय उत्पादन में 69.12 प्रतिशत सामूहिक हिस्सा है, जैसाकि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

### भारतीय उत्पादकों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
क.	याचिकाकर्ता कंपनी					
1.	कैम्प्लास्ट सनमार लिमिटेड	मी.ट.	***	***	***	***
2.	गुजरात फ्लोरोकैमिकल लिमिटेड	मी.ट.	***	***	***	***
	आवेदकों की कुल संख्या	मी.ट.	70,459	71,365	74,650	71344
ख	सहयोगी					
	टीजीवी सार्क लि.	मी.ट.	***	***	***	***
ग.	अन्य भारतीय उत्पादक	मी.ट.				
1.	गुजरात अल्कलीज एंड कैमिकल लिमिटेड	मी.ट.	***	***	***	***
2.	एसआरएफ लिमिटेड	मी.ट.	***	***	***	***

	अन्य भारतीय उत्पादकों का योग	मी.ट.	39,271	39,636	41,724	41,733
	कुल भारतीय उत्पादक	मी.ट.	<b>1,09,730</b>	<b>1,11,000</b>	<b>1,33,572</b>	<b>1,35,125</b>
	उत्पादन में हिस्सा					
	आवेदक कंपनी	%	64.21	64.29	55.89	52.80
	सहयोगी	%	-	-	***	***
	अन्य घरेलू उत्पादक	%	35.79	35.71	31.24	30.88
	कुल	%	100	100	100	100

22. इसके अतिरिक्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उन्हें जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का आयात करते हुए नहीं पाया गया है और नियम 2 (ख) के अभिप्राय से उन्हें संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं पाया गया है।

23. उपर्युक्त के मद्देनजर और उचित जांच के बाद प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक आधार की अपेक्षाएं पूरी करते हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) तथा नियम 5(3) के तहत घरेलू उद्योग हैं।

#### **ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे**

##### **ड.1 प्राधिकारी द्वारा जांच**

24. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

25. गोपनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

#### **च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**

##### **च.1 संबद्ध देश में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण**

26. सामान्य मूल्य से संबंधित प्रावधान अधिनियम की धारा 9 क (1)(ग) में और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 में दिए गए हैं। सीमा प्रशुलक अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (1)(ग) के अनुसार वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य है:

- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई विक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम विक्री मात्रा के कारण ऐसी विक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-  
(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

27. संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं। संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों से असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने में सक्षम नहीं हैं और सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के सिद्धांतों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए मजबूर हैं। प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। तदनुसार, निर्मित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाए गए अनुसार निर्धारित किया गया है।
28. प्राधिकारी ने उत्पादन की ईष्टतम लागत पर विचार करके और बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागत तथा उचित लाभ देने के बाद संबद्ध देशों में सभी निर्यातकों द्वारा निर्यातित संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

## च.2 संबद्ध देशों में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

29. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत डी जी सी आई एंड एस के लेनदेनवार आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की है। कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए निर्यात कीमत को भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय के निमित्त समायोजित किया गया है। तदनुसार, संबद्ध देशों से निर्यातों के लिए कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गई है।

## च.3 संबद्ध देशों में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण

30. उपर्युक्तानुसार, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के सभी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	संयुक्त राज्य	यूरोपीय संघ
1क	आयात मात्रा पैकड	मी.ट.	शून्य	0.41
1ख	आयात मात्रा लूज	मी.ट.	4,347	10,413
1	<b>कुल आयात</b>	मी.ट.	<b>4,347</b>	<b>10,414</b>
2क	निर्मित सामान्य मूल्य – पैकड	रु./मी.ट.	***	***
2ख	निर्मित सामान्य मूल्य लूज	रु./मी.ट.	***	***
2	सीएनवी- भारित औसत	रु./मी.ट.	***	***
3 क	एनईपी पैकड	रु./मी.ट.	***	***
3 ख	एनईपी लूज	रु./मी.ट.	***	***
3	निवल निर्यात कीमत (भा.औ.)	रु./मी.ट.	***	***



4क	पाटन मार्जिन	रु./मी.ट.	***	***
4ख	पाटन मार्जिन	अम.डॉ./मी.ट.	***	***
4ग	पाटन मार्जिन	%	***	***
4घ	पाटन मार्जिन	रेंज	90-100	75-85

## छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क

### छ.1 घरेलू उद्योग के विचार

31. वर्तमान जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा क्षति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं जिनको प्राधिकारी ने संगत माना है :
  - i. मूल जांच के असमान निर्णायक समीक्षाएं प्रकृति में संभावनी हैं क्योंकि वे, यदि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाते हैं तो पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना पर जोर देते हैं।
  - ii. क्षति निर्धारण के संबंध में यदि पाटनरोधी शुल्क का वांछित प्रभाव होता है तो घरेलू उद्योग की स्थिति पाटनरोधी शुल्क लागू रहने की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग में सुधार की उम्मीद की जाती। अतः यह निर्धारण कि क्या क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी, पाटित आयातों, कीमतों और घरेलू उद्योग पर प्रभाव के अनुमानित स्तरों के आधार पर भावी घटनाओं का प्रति-वास्तविक विश्लेषण होगा।
  - iii. यूरोपीय संघ से आयात 2015-16 में बढ़े जोकि आधार वर्ष के बाद का वर्ष है। वह जांच की अवधि तक और उस अवधि सहित कम हुआ। तथापि, वह पूरी क्षति अवधि में काफी रहा।
  - iv. संयुक्त राज्य अमरीका से पूरी क्षति की अवधि में आयात कम हुए परंतु आयात कीमत भी वही रही। तथापि, वह क्षति की पूरी अवधि में काफी रही।
  - v. आयातों में वर्तमान गिरावट मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण है। संबद्ध देशों से आयात हर संभावना में पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पूर्व के स्तरों को पुनः प्राप्त करेंगे।
  - vi. भारतीय मांग में संबद्ध आयातों का हिस्सा पूरी क्षति की अवधि में कम हुआ है।
  - vii. यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के मामले में आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि सहित पूरी क्षति की अवधि में निवल बिक्री वसूली से वास्तविक रूप से कम है।
  - viii. पैकड स्वरूप के आयातों के मामले में कीमत कटौती में पूरी क्षति अवधि में गिरावट आई और आयातों की नगण्य मात्रा के कारण जांच की अवधि में नकारात्मक थी।
  - ix. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का हास हुआ और कीमतों में वृद्धि में रूकावट आई जोकि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटन न होने पर हुई होती।
  - x. उत्पादन क्षति की अवधि में थोड़ा सा बढ़ा है परंतु पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वह कम हुआ है।
  - xi. घरेलू बिक्री क्षति की अवधि में बढ़ी है परंतु पूर्व वर्ष की तुलना में वह जांच की अवधि में कम हुई है।
  - xii. जांच की अवधि में क्षमता उपयोग कुल मिलाकर आधार वर्ष की तुलना में समान स्तर पर है परंतु पूर्व वर्ष से तुलना करने पर वह कम हुई है। औसत उद्योग मानदंड 95-100 प्रतिशत है।
  - xiii. लाभप्रदता, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय पूरी क्षति अवधि में कम हुई है और काफी मात्रा तक हुई है।
  - xiv. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि में गिरावट आई।
  - xv. घरेलू उद्योग में माल सूची में क्षति की अवधि में कुछ वृद्धि हुई है।
  - xvi. रोजगार स्तर क्षति की अवधि में स्थिर रहा है। क्षति की अवधि में दी गई मजदूरी में वृद्धि हुई है।
  - xvii. प्रति दिन उत्पादकता में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, इसके बावजूद घरेलू उद्योग निवेश पर अपेक्षित आय अर्जित करने में सक्षम नहीं है और उसमें क्षति की अवधि में गिरावट आई है।
  - xviii. पूंजी निवेश जुटाने में घरेलू उद्योग की क्षमता पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में लड़खड़ा जाएगी।

- xix. संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ के मामले में क्षति मार्जिन केवल नकारात्मक ही नहीं है बल्कि काफी भी है।
- xx. संबद्ध सामानों की मांग/स्पष्ट खपत क्षति की अवधि में बढ़ी है। जांच की अवधि में मांग आधार वर्ष की अपेक्षा 15 प्रतिशत अधिक है।
32. घरेलू उद्योग ने कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-
- कारणात्मक संपर्क मूल जांच में पहले ही सिद्ध किए जा चुके हैं।
  - यह कानून की निर्धारित स्थिति है कि कारणात्मक संपर्क विश्लेषण निर्णायक समीक्षा जांच में किए जाने के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका –ओसीटीजी में डब्ल्यू टी ओ अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में यह माना गया है कि निर्णायक समीक्षा निर्धारण में कानूनी दायित्व के मामले के रूप में संभावित पाटन एवं संभावित क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी सिद्ध करने की कोई अपेक्षा नहीं है।
  - अन्य देशों से उत्पाद के आयातों पर या तो पाटनरोधी शुल्क लग रहा है या वे मात्रा में काफी नहीं हैं अथवा संबद्ध देशों की कीमतों से अधिक कीमतों पर हैं।
  - मांग में गिरावट नहीं है और इसीलिए मांग में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारक नहीं है।
  - कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां अथवा प्रौद्योगिकी के मुद्दे नहीं हैं जिन्हें घरेलू उद्योग को क्षति का कारण माना जा सके।
  - घरेलू बिक्री को क्षति निर्यातों के कारण नहीं हो सकती।
  - घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति जांच अवधि में वृद्धि हुई है। अतः उत्पादकता घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।
- छ.2 **अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**
33. चूंकि घरेलू उद्योग के अलावा किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस जांच में भाग नहीं लिया है, अतः प्राधिकारी के लिए विचार करने हेतु अन्य हितबद्ध पक्षकारों के कोई अनुरोध नहीं हैं।
- छ.3 **प्राधिकारी द्वारा जांच**
34. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों की जांच एवं समाधान निम्नलिखित रूप में किया गया है।
35. प्राधिकारी ने मात्रात्मक प्रभाव और कीमत प्रभाव दोनों की जांच कर क्षति का मूल्यांकन किया है। क्षति के निर्धारण में (क) समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा पाटित आयातों की मात्रा और (ख) घरेलू उद्योग पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की वस्तुपरक जांच शामिल होती है।
- छ.2.1 **पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव**
- (क) **मांग का निर्धारण**
36. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री की मात्रा और सभी स्रोतों से आयातों के रूप में भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को परिभाषित किया है। इस प्रकार, मूल्यांकित मांग निम्नलिखित तालिका में दी गई है :-

मांग और बाजार हिस्सा

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
सहयोगियों सहित अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***

संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	25,784	26,061	22,290	14,761
अन्य देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है।	मी.ट.	27,295	69,146	40,847	39,463
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	13,396	7,476	13,867	16,651
<b>कुल मांग</b>	मी.ट.	<b>1,77,212</b>	<b>2,10,488</b>	<b>2,06,520</b>	<b>2,03,278</b>
<b>प्रवृत्ति</b>	<b>सूचीबद्ध</b>	<i>100</i>	<i>119</i>	<i>117</i>	<i>115</i>

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2014-15 से 2015-16 में विचाराधीन उत्पाद की मांग काफी बढ़ी है और उसके बाद 2016-17 तथा जांच की अवधि में कम हुई है।

**(ख) संबद्ध देशों का हिस्सा और आयात मात्रा**

38. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के अनुपात में काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है :

**आयात और बाजार हिस्सा**

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
1.क	ई यू से आयात	मी.ट.	12,936	18,997	15,482	10,414
1.ख	यूएसए से आयात	मी.ट.	12,848	7,064	6,808	4,347
1	संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	<i>25,784</i>	<i>26,061</i>	<i>22,290</i>	<i>14,761</i>
2	<b>कुल मांग</b>	मी.ट.	1,77,212	2,10,488	2,06,521	2,03,278
3	कुल भारतीय उत्पादन	मी.ट.	1,09,730	1,11,000	1,33,572	1,35,124
	<b>की तुलना में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा</b>					

3.	भारत में मांग	%	14.55	12.39	10.79	7.26
4.	भारत में उत्पादन	%	23.50	14.47	16.69	10.92

39. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि :

- संबद्ध देशों से आयातों में क्षति की अवधि में 2016-17 को छोड़कर गिरावट आई है।
- भारत में खपत की तुलना में संबद्ध आयातों का हिस्सा 2014-15 से 2015-16 में काफी कम हुआ है। उसके बाद जांच की अवधि में 7.26 प्रतिशत तक कम होने से पहले 2016-17 में इसमें वृद्धि हुई।
- भारत में उत्पादन की तुलना में संबद्ध आयातों का हिस्सा क्षति की अवधि में 2016-17 को छोड़कर कम हुआ है। भारत में उत्पादन की तुलना में संबद्ध आयातों का हिस्सा जांच की अवधि में 10.92 प्रतिशत तक गिरा है।

### छ.3.1

40. क्षति की अवधि में संबद्ध देशों से आयात कीमत कम हुई है जोकि निम्नलिखित तालिका में देखी जाएगी। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आयात कीमत में 21 प्रतिशत की गिरावट है। संबद्ध देशों से आयात कीमतें उन देशों से और अन्य देशों से भी काफी कम हैं जिन पर पहले ही पाटनरोधी शुल्क लग रहा है।

### सीआईएफ आयात कीमत

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
1	संबद्ध देशों से आयात	रु./मी.ट.	34,229	28,303	25,310	27,208
(i)	ईयू	रु./मी.ट.	36,645	28,247	25,720	27,288
(ii)	यूएसए	रु./मी.ट.	31,796	28,453	24,376	27,015
2	अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	रु./मी.ट.	41,270	35,248	27,036	28,638
3	शेष देशों से आयात	रु./मी.ट.	38,531	33,879	32,138	31,627

### छ.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

41. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत ने समान उत्पाद की कीमत से तुलना करने पर पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का हास करने के लिए अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए अन्यथा है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

#### (क) कीमत कटौती

42. इस संबंध में संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पहुंच मूल्य और व्यापार के समान स्तर पर सभी निवल छूटों और करों पर घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमत कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई थी। घरेलू कीमतें और कटौती का मार्जिन निम्नलिखित तालिका के अनुसार दर्शाया गया है :

**कीमत कटौती**

क्र.सं.	विवरण	इकाई	ई यू	यू एस ए	संबद्ध देश
1.	ए डी डी रहित आयातों की पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	29,690	29,393	29,603
2.	भारत में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.ट.	***	***	***
3.क	ए डी डी रहित कीमत कटौती	रु./मी.ट.	***	***	***
3.ख	ए डी डी रहित कीमत कटौती	%	***	***	***
3.ग	ए डी डी रहित कीमत कटौती	रेंज	20-30	20-30	20-30
4.	पाटन रोधी शुल्क	रु./मी.ट.	21,142	21,802	21,336
4.क	ए डी डी सहित कीमत कटौती	रु./मी.ट.	***	***	***
4.ख	ए डी डी सहित कीमत कटौती	%	***	***	***
4.ग	ए डी डी सहित कीमत कटौती	रेंज	(20-30)	(20-30)	(20-30)

43. यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका से संबद्ध सामानों के आयातों से कीमत कटौती (पाटनरोधी शुल्क शामिल किए बिना) सकारात्मक और काफी है। जब पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत में शामिल किया जाता है तो यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका दोनों के लिए कीमत कटौती नकारात्मक हो जाती है।

**(ख) कम कीमत पर बिक्री**

44. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई कम कीमत पर बिक्री की जांच भी की है। इस प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है। आयातों की भारित औसत पहुंच कीमत से घरेलू उद्योग की एनआईपी की तुलना निम्नलिखित रूप में दर्शायी गई है :—

**कम कीमत पर बिक्री**

क्र.सं.	विवरण	इकाई	ई यू	यू एस ए	संबद्ध देश
1.	ए डी डी रहित आयातों की पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	29,690	29,393	29,603
2.	क्षति रहित कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***
3.क	कम कीमत पर बिक्री	रु./मी.ट.	***	***	***
3.ख	कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***
3.ग	कम कीमत पर बिक्री	रेंज	40-50	40-50	40-50

45. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक और काफी है।

**(ग) पाटित आयातों का कीमत ह्रास और न्यूनीकरण**

46. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास हो रहा है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों का काफी मात्रा तक न्यूनीकरण करना अथवा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया है।

**कीमत ह्रास/न्यूनीकरण**

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
ए डी डी रहित पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	37,651	31,121	27,395	29,603
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	73	79
प्रति इकाई बिक्री की लागत- घरेलू बिक्री	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	101	112
प्रति इकाई बिक्री कीमत - घरेलू बिक्री	रु./मी.ट.	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	84	90
-----------	----------	-----	----	----	----

47. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि :

- संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य में क्षति की अवधि में गिरावट आई है, केवल जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- घरेलू उद्योग की बिक्री लागत आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 12 प्रतिशत तक बढ़ी है।
- घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 10 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।
- इस प्रकार कीमत ह्रास तथा कीमत न्यूनीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है।

#### मात्रा तथा कीमत प्रभाव संबंधी निष्कर्ष

48. यद्यपि इस अवधि में आयातों की मात्रा में गिरावट आई तथापि वह उत्पादन और खपत के संबंध में तथा पूर्ण दृष्टि से काफी रही है। आयात कीमत भी जांच की अवधि में आंशिक रूप में बढ़ने से पूर्व क्षति की अवधि में कम हुई है। ऐसे पाटित आयातों का प्रभाव कीमतों का ह्रास करने के लिए तथा कीमत वृद्धि रोकने के लिए रहा है जो अन्यथा हुई होती।

#### छ.3.3 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंडों की जांच

49. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादकों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

50. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंड ह्रास दर्शाएं। कुछ मापदंड ह्रास दर्शा सकते हैं; जबकि कुछ सुधार दर्शा सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी सभी क्षति मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा नहीं। प्राधिकारी ने अनुरोधों में दिए गए तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए तथ्यपरक रूप से क्षति मापदंडों की जांच की है।

51. तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों का विश्लेषण यहां निम्नलिखित रूप में किया गया है :

#### (क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

52. उत्पादन, क्षमता क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित था :

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
1.	क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
2.	उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
3.	क्षमता उपयोग	%	89	90	94	90
4.	घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***

53. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि :

- घरेलू उद्योग की क्षमता पूरी क्षति जांच अवधि में स्थिर रही है।
- उत्पादन जांच की अवधि को छोड़कर पूरी क्षति अवधि में बढ़ा है, जब उत्पादन पूर्व वर्ष की तुलना में कम हुआ है।
- घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान बहुत अच्छा रहा है।
- घरेलू बिक्री की मात्रा जांच की अवधि में थोड़ी सी गिरावट के साथ पूरी क्षति अवधि में बढ़ा है।

**(ख) बाजार हिस्सा**

54. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के बाजार हिस्से की जांच निम्नलिखित रूप में की गई है :

**मांग में बाजार हिस्सा**

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	40.36	32.97	35.76	36.13
सहयोगियों सहित अन्य उत्पादकों का हिस्सा	%	22.13	18.24	26.95	29.01
घरेलू उत्पादकों का हिस्सा	%	62.49	51.21	62.71	65.14
संबद्ध देशों का हिस्सा	%	14.55	12.39	10.79	7.26
समस्त अन्य देशों का हिस्सा	%	22.96	36.41	26.5	27.6
कुल	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

55. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2015-16 में गिरावट आई और उसके बाद सुधार होता रहा है।
- अन्य घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में 2015-16 में गिरावट आई और उसके बाद सुधार होता रहा है।
- संबद्ध देशों से आयात के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि में निरंतर गिरावट आई है।



**(ग) मालसूची**

56. संबद्ध सामानों की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं :

**मालसूची**

विवरण	यूओएम	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	138	264	136
उत्पादन के दिवसों के अनुसार मालसूची	मी.ट./ दिवस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	138	264	136
बिक्री के दिवसों के अनुसार मालसूची	मी.ट./ दिवस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	138	264	136

57. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि :

- औसत मालसूची जांच की अवधि में गिरावट को छोड़कर पूरी क्षति की अवधि में बढ़ी ।
- उत्पादन और बिक्री दोनों की दृष्टि से प्रति दिन मालसूची में वही प्रवृत्ति रही ।

**(घ) लाभ निवेश पर आय और नकद प्रवाह**

58. घरेलू उद्योग के लाभ/हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है :

**लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह**

विवरण	यूओएम	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
प्रति इकाई पीबीआईटी – घरेलू बिक्री	लाख रूपए	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	53	20	13
प्रति इकाई पीबीआईटी – घरेलू बिक्री	रु./ मी.ट.	***	***	***	***

सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	55	19	13
नकद प्रवाह	लाख रूपए	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	24	20	55
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	66	22	17

59. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि :

- घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों में क्षति की अवधि में गिरावट आई है।
- घरेलू उद्योग के लिए पीबीआईटी में क्षति की अवधि में काफी गिरावट आई है। घरेलू बिक्री की प्रति इकाई पीबीआईटी के लिए समान प्रवृत्ति देखी जा सकती है।
- घरेलू उद्योग द्वारा कमाए गए नकद लाभ में क्षति की अवधि और जांच की अवधि में निरंतर गिरावट आई है।
- घरेलू उद्योग ने 2014-15 में नियोजित पूंजी पर अच्छी आय अर्जित की। तथापि, उसमें क्षति की अवधि और जांच की अवधि में निरंतर गिरावट आई।

#### (ड.) रोजगार और उत्पादकता

60. आवेदकों द्वारा नियुक्त कार्मिकों की संख्या और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नलिखित है :

#### रोजगार और उत्पादकता

विवरण	यूओएम	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	97	96	97
प्रति दिवस उत्पादकता	मी.ट./दिवस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	101	106	101

61. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि :

- घरेलू उद्योग द्वारा नियुक्त कार्मिकों की संख्या लगभग समान रही है।
- घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी क्षति की अवधि में आंशिक अंतर आया है।

(च) वृद्धि

विवरण	यूओएम	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
उत्पादन मात्रा	%	-	1.29	4.60	(4.43)
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति		100	358	(345)
घरेलू बिक्री मात्रा	%	-	(2.96)	6.42	(0.58)
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति		(100)	217	(19)
प्रति इकाई घरेलू बिक्री की बिक्री लागत	%	-	(4.09)	5.74	10.38
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति		(100)	140	254
प्रति इकाई घरेलू बिक्री की बिक्री लागत	%	-	(13.00)	(4.69)	8.32
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति		(100)	(36)	64
पीबीआईटी प्रति इकाई घरेलू बिक्री	%	-	(41.83)	(59.33)	(36.91)
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति		(100)	(142)	(88)
पीबीआईटी प्रति इकाई घरेलू बिक्री	%	-	(44.93)	(64.65)	(33.43)
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति		(100)	(144)	(74)
आरओसीई प्रति इकाई घरेलू बिक्री	%	-	(33.92)	(66.04)	(23.05)
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति		(100)	(195)	(69)

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वृद्धि उपर्युक्त सभी मापदंडों के लिए जांच की अवधि में नकारात्मक रही है।

(छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

63. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत या रिकार्ड में उपलब्ध कोई सत्यापनीय सूचना नहीं है। इस प्रकार, प्राधिकारी पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते।

**ज. क्षति मार्जिन की मात्रा**

64. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों की निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना जांच की अवधि में क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों से निर्यातों के पहुंच मूल्य से निम्नलिखित रूप में की गई है :

**क्षति मार्जिन**

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	संयुक्त राज्य	यूरोपीय संघ
1क	आयात मात्रा पैकड	मी.ट.	शून्य	0.41
1ख	आयात मात्रा लूज	मी.ट.	4,347.27	10,413.46
1	<b>कुल आयात</b>	मी.ट.	4,347.27	10,413.87
2क	एनआईपी पैकड	अम.डा./मी.ट.	***	***
2ख	एनआईपी लूज	अम.डा./मी.ट.	***	***
2	एनआईपी – भारित औसत	अम.डा./मी.ट.	***	***
3क	पहुंच मूल्य पैकड	अम.डा./मी.ट.	***	***
3ख	पहुंच मूल्य लूज	अम.डा./मी.ट.	***	***
3	पहुंच मूल्य औसत	अम.डा./मी.ट.	444.89	449.391
4क	क्षति मार्जिन	अम.डा./मी.ट.	***	***
4ख	क्षति मार्जिन	%	***	***
4ग	क्षति मार्जिन	रेंज	40-50	40-50

**झ. क्षति सामग्री संबंधी निष्कर्ष**

65. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

- (क) संबद्ध देशों से आयात यद्यपि, क्षति की अवधि में कम हुए परंतु फिर भी वे काफी नहीं थे।
- (ख) आयातों की पहुंच कीमत में क्षति की अवधि में गिरावट आई है और जांच की अवधि में थोड़ी सी वृद्धि हुई है।
- (ग) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की काफी कटौती कर रहे हैं।
- (घ) आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का हास हुआ है और वे कीमतें बढ़ने से रूकी हैं जो अन्यथा हो सकती थीं।

(ड.) पूरी क्षति की अवधि में लाभप्रदता, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय में गिरावट आई है और काफी सीमा तक आई है।

(च) क्षति मार्जिन केवल सकारात्मक ही नहीं है बल्कि काफी भी है।

66. इस प्रकार, घरेलू क्षति से पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के बावजूद कीमत संबंधी क्षति जारी रही है।

**झ. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना :**

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इस जांच का जोर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की अनुमति दिए जाने पर पाटन और क्षति के बार-बार होने अथवा जारी रहने की संभावना की जांच करने पर है।

**झ1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

68. घरेलू उद्योग ने पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:—

- i. पाटन की संभावना से संगत कारक क्षति की संभावना तथा वर्तमान मामले में संगत है।
- ii. भारतीय बाजार को निर्यात पाटित कीमतों पर किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ से पाटन जारी रहे हैं।
- iii. वर्तमान जांच की अवधि में पाटन तथा क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी हैं।
- iv. विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों के बिना कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है।
- v. आयातों की वर्तमान मात्रा स्वयं में संभावना सिद्ध करने के लिए काफी है।
- vi. इसका पर्याप्त साक्ष्य है कि आयातों की मात्रा पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में काफी बढ़ेगी।
- vii. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य काफी उत्पादन क्षमता है जो यह सिद्ध करती है कि शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में भारत को निर्यात काफी होंगे।
- viii. आयात कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से काफी कम हैं। अतः उपभोक्ता आयातित उत्पादों की ओर चले गए। पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में उत्पाद के आयातों में काफी वृद्धि होगी।
- ix. घरेलू उद्योग को कीमत संबंधी क्षति हो रही है। पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने से कम से कम घरेलू उद्योग को क्षति और होगी।
- x. संबंधित निर्यातकों की भारी अतिरिक्त क्षमताओं और उनकी आक्रामक निर्यात नीति के मद्देनजर यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क संरक्षण समाप्त किया जाता है, तो घरेलू उद्योग को भारी नुकसान उठाना ही पड़ेगा।
- xi. इसका पर्याप्त साक्ष्य है कि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने के बाद संबद्ध देशों के निर्यातक संबद्ध सामानों का निर्यात पाटित और क्षति कारक कीमतों पर करेंगे।

**झ.2 प्राधिकारी द्वारा जांच**

69. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-II (vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे के विशेष संदर्भ में पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग के तर्कों की जांच की है।

**(क) पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की महत्वपूर्ण दर**

70. वर्तमान क्षति अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से निरंतर काफी गिरावट आई है।

**(ख) कोई अतिरिक्त निर्यात लेने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजारों में काफी बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त स्वतंत्र निपटान योग्य, अथवा आसन्न, पर्याप्त वृद्धि।**

71. वास्तविक क्षति/ क्षति के बार बार होने की संभावना का खतरा सुनिश्चित करने के लिए इस मापदंड हेतु भारतीय बाजार में निपटान योग्य मात्रा को बदलने की संभावना का पता लगाने के लिए मौजूदा अतिरिक्त क्षमताओं तथा क्षमता, अभिवृद्धि यदि कोई है, का मूल्यांकन अपेक्षित होता है।

72. घरेलू उद्योग ने पी एंड एस बाजार अनुसंधान द्वारा दिए गए अनुसार मिथाइलीन क्लोराइड संबंधी बाजार अनुसंधान रिपोर्ट से संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों की मांग, उत्पादन और बिक्री के संबंध में सूचना एकत्रित की है।

73. प्राधिकारी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर यह नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ में सभी उत्पादकों की कुल क्षमताएं 9,43,100 मी.ट. है जबकि यूरोपीय संघ ने संबद्ध सामानों के लिए घरेलू मांग 2,90,100 मी.ट. है । यूरोपीय संघ में निर्यात योग्य अधिशेष 6,53,000 मी.ट. आकलित किया गया है ।
74. प्राधिकारी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर यह नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका में सभी उत्पादकों की कुल क्षमताएं 2,01,400 मी.ट. है जबकि संयुक्त राज्य अमरीका ने संबद्ध सामानों के लिए घरेलू मांग 1,19,500 मी.ट. है । संयुक्त राज्य अमरीका में निर्यात योग्य अधिशेष 81,900 मी.ट. आकलित किया गया है ।
- (ग) क्या आयात उन कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासमान अथवा न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा और जिनसे और आयातों के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी।
75. संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य में क्षति की अवधि में गिरावट आई है, जांच की अवधि में केवल आंशिक वृद्धि हुई है ।
76. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 12 प्रतिशत तक बढ़ी है ।
77. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 10 प्रतिशत तक की गिरावट आई है ।
78. संबद्ध देशों से आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण तथा ह्रासमान प्रभाव पड़ रहा है ।
- (घ) जांच की जा रही वस्तु की मालसूची
79. रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों में यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका में निर्यातकों के पास विचाराधीन उत्पाद की मालसूची के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है ।
- ट. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध
- ट.1 प्राधिकारी द्वारा जांच
80. यह भी जांच की गई कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध निम्नलिखित अन्य मापदंडों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है । निम्नलिखित रूप में नोट किया गया है:
- (क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें
81. आयात की कीमतें अधिक होने के नाते अन्य देशों से संबद्ध सामानों के आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती ।
- (ख) मांग में संकुचन और खपत की पद्धति में परिवर्तन
82. क्षति की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग/स्पष्ट खपत में वृद्धि हुई है और मांग में संकुचन क्षति का कारक नहीं हो सकता ।
- (ग) प्रौद्योगिकी में विकास
83. संबंधित उत्पाद की उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।
- (घ) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और प्रतिस्पर्धा
84. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित हो सके ।
- (ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन
85. प्राधिकारी द्वारा केवल घरेलू प्रचालनों को ध्यान में रखते हुए ही क्षति विश्लेषण किया गया है । अतः निर्यात बाजार में निष्पादन से वर्तमान क्षति विश्लेषण प्रभावित नहीं हुआ है ।
- (च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता
86. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति जांच अवधि में केवल आंशिक परिवर्तन आया है ।
- ज.2 प्राधिकारी द्वारा जांच
87. कारणात्मक संपर्क स्थापित करने वाले कारक
- (क) संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ से आयात पाटित कीमतों पर जारी रहे हैं ।
- (ख) आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हो रही है । घरेलू उद्योग को भी पाटित आयातों के कारण उसकी कीमतों पर न्यूनीकरण एवं ह्रासमान प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है ।
- (ग) कीमत न्यूनीकरण/ह्रास से घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में ह्रास हुआ है ।
- (घ) संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास मुक्त रूप से काफी निपटान योग्य उत्पादन क्षमताएं हैं। पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हो सकती है ।
- ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां
- ठ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

88. घरेलू उद्योग ने अपने प्रकटन पश्चात् अनुरोधों में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं। संक्षिप्तता के लिए घरेलू उद्योग द्वारा की गई टिप्पणियां पूर्व में अनुरोधों की पुनरावृत्ति की सीमा तक तथा ऊपर पहले ही हल की गई सीमा तक पुनः यहां नीचे नहीं दोहराई गई है।
- (क) वास्तविक पाटन मार्जिन प्रकट नहीं किया गया है जिसके कारण टिप्पणियां करने के लिए प्रभावी अवसर नहीं दिया गया है।
- (ख) प्राधिकारी शुल्क तालिका में कृपया उल्लेख कर सकते हैं कि संबद्ध सामानों पर उन सीमा शुल्क वर्गीकरणों पर ध्यान न देते हुए शुल्क लगता है जिसके तहत इनका आयात किया जाता है।
- (ग) किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। इस प्रकार, प्राधिकारी निर्यातकों को असहयोगी मान सकते हैं और नियम 6(8) के अनुसार मामले में निर्णय ले सकते हैं।
- (घ) यद्यपि, प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-ii(vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे के लिए मापदंडों के विशेष संदर्भ में पाटन एवं क्षति जारी रहने की संभावना की जांच की तथापि, उन्होंने घरेलू उद्योग के निम्नलिखित अनुरोधों को न तो स्वीकार किया और न ही उन पर विचार किया और न ही उनका समाधान किया।
- (i) मूल जांच और वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन एवं क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी हैं।
- (ii) यूरोपीय संघ में घरेलू मांग यूरोपीय संघ में कुल क्षमताओं की केवल 30.76 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध सामानों की यूरोपीय संघ में क्षमता कुल भारतीय क्षमता की 1185.42 प्रतिशत, भारतीय उत्पादन की 1321.92 प्रतिशत और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री की 1284.23 प्रतिशत है।
- (iii) अतिरिक्त उत्पादन जो यूरोपीय संघ में प्रमुख उत्पादकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अर्थात् अक्जो नोबल और आईएनईओएस भारतीय मांग का 36 प्रतिशत है। यूरोपी संघ में अन्य उत्पादक भी हैं।
- (iv) इसी प्रकार, संयुक्त राज्य अमरीका में घरेलू मांग संयुक्त राज्य अमरीका में कुल क्षमताओं की केवल 59 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमरीका में संबद्ध सामानों की क्षमता कुल भारतीय क्षमता की 253.5 प्रतिशत, भारतीय उत्पादन की 282.30 प्रतिशत और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री की 274.25 प्रतिशत है।
- (v) अतिरिक्त उत्पादन जो संयुक्त राज्य अमरीका में प्रमुख उत्पादकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है भारतीय मांग का 29 प्रतिशत है। संयुक्त राज्य अमरीका में अन्य उत्पादक भी हैं।
- (vi) संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ में उत्पादक तथा निर्यातक निर्यातोन्मुख हैं और उन्होंने क्रमशः अपनी क्षमताओं का लगभग 34 प्रतिशत और 16 प्रतिशत विश्व को निर्यात किया है।
- (vii) यूरोपीय संघ में संबद्ध सामानों के उत्पादक अग्नोनोबल ने क्लोरोमिथेन के उत्पादन के लिए जर्मनी में अगले विस्तार के डिजाइन चरण में प्रवेश कर लिया है।
- (viii) यद्यपि, पेंट स्ट्रीपर में मिथाइलीन क्लोराइड का प्रयोग हाल ही में यूरोपीय संघ में प्रतिबंधित किया गया है, तथापि, वही संयुक्त राज्य अमरीका में भी होने जा रहा है। इस प्रकार, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका में कमजोर पड़ रही मांग से संबद्ध सामानों का निर्यातों में परिवर्तन होगा।
- (ix) भारत निर्यातकों के लिए आकर्षक बाजार है। एशिया प्रशांत विभिन्न अंतिम प्रयोक्ता उद्योगों से घोलों की बढ़ती हुई मांग के कारण मिथाइलीन क्लोराइड के लिए तेजी से बढ़ते हुए बाजारों में से एक बाजार होने की उम्मीद है। भारत और पाकिस्तान का एशिया प्रशांत क्षेत्र में मिथाइलीन क्लोराइड के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार हिस्सा है। भारत इस क्षेत्र में मिथाइलीन क्लोराइड के लिए तेजी से बढ़ता हुआ देश होने की संभावना है।
- (x) यहां तक कि यदि संभावना की एक स्थिति पूरी की जाती है तो शुल्क समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह प्राधिकारी की सतत परिपाटी रही है।
- (ड.) यद्यपि प्राधिकारी ने पहुंच कीमत तथा बिक्री कीमत में कीमत अंतर के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे को स्वीकार किया है, तथापि, उन्होंने इस मुद्दे को हल नहीं किया है। इस मापदंड का विश्लेषण भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण है। कीमत में अंतर इस बात को सिद्ध करता है कि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार और कीमतें विदेशी उत्पादकों के लिए काफी आकर्षक हो जाएंगी और विदेशी उत्पादकों को उनके निर्यात बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की संभावना है।
- (च) वास्तविक क्षति के खतरे के मापदंड संभावना के निर्धारण से संगत मापदंडों की ऊपरी सीमा नहीं हैं तथा यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी खतरे के मापदंडों के आधार पर संभावना के अपर्याप्त साक्ष्य पाते हैं तो निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए अन्य मापदंडों पर विचार करना अपेक्षित है।

- (छ) जारी किए गए प्रकटन विवरण में प्राधिकारी ने नियमावली के तहत सूचीबद्ध मापदंडों की जांच की है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। प्रकट किए गए तथ्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि किसी भी सूचीबद्ध मापदंड से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। फिर भी, याचिकाकर्ताओं का अनुरोध है कि प्राधिकारी ने कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निम्नलिखित अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया है:
- (i) यह कानून की एक निर्धारित स्थिति है कि कारणात्मक संपर्क विश्लेषण निर्णायक समीक्षा जांच में अनिवार्य रूप से किया जाना अपेक्षित है। इसकी पुष्टि मेक्सिको से आयल कंट्री ट्यूबलर गुड्स में अपीलीय निकाय द्वारा (डब्ल्यूटी/डीएस282/एबी/आरदिनांक 2 नवंबर, 2005) की गई है।
  - (ii) यूएस-डीआरएमएस मामले में भी डब्ल्यू टी ओ पैनल का मत था कि कारणात्मक संपर्क विश्लेषण निर्णायक समीक्षा जांच में अपेक्षित कारक नहीं है।
  - (iii) अन्य देशों से उत्पाद के आयातों पर या तो पाटनरोधी शुल्क लग रहा है अथवा वे मात्रा में कम हैं अथवा संबद्ध देशों की कीमतों से अधिक कीमतों पर हैं।
  - (iv) संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ से आयात पाटित कीमतों पर जारी रहे हैं और घरेलू कीमतों से कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। इस प्रकार, यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो पाटित आयातों की मात्रा और भी अधिक हो जाएगी।
  - (v) शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों की काफी कटौती होगी। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को जिसको पहले ही अपनी कीमतों पर न्यूनीकरण तथा ह्रासमान प्रभाव पड़ रहा है, पाटनरोधी शुल्क आगे न बढ़ाए जाने की स्थिति में और भी न्यूनीकरण तथा ह्रासमान प्रभाव का सामना करना पड़ेगा।
  - (vi) कीमत न्यूनीकरण और ह्रास से घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में ह्रास हुआ है। पाटनरोधी शुल्क बंद करने के परिणामस्वरूप लाभ में और अधिक गिरावट आएगी और परिणामस्वरूप नियोजित पूंजी पर आय तथा नकद लाभ में भी गिरावट आएगी।
  - (vii) संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य काफी उत्पादन क्षमताएं हैं। पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटित आयातों की मात्रा और अधिक बढ़ेगी।
  - (viii) यदि शुल्क बंद किया जाता है और परिणामस्वरूप संबद्ध देशों से आयात बढ़ते हैं तो घरेलू उद्योग संबंधित उत्पाद की कीमतों को काफी कम करने के लिए मजबूर होगा और लाभप्रदता निरंतर घटती जाएगी। इससे नकद प्रवाह, निवेश पर आय में और भी गिरावट आएगी।  
यदि घरेलू उद्योग अपनी सामान्य कीमत स्तरों को बनाए रखने का विकल्प चुनता है तो उसकी बिक्री की मात्रा समाप्त होने की संभावना है क्योंकि उपभोक्ता बढ़चढ़कर आयातों की ओर जाएंगे।
- (ज) घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे कृपया इस मामले में निष्कर्ष निकालते समय उपर्युक्त में विचार करें।
- (झ) नियमावली में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक कारक को सिद्ध करने की स्पष्ट अपेक्षा है।
- क. पाटन और क्षति का जारी रहना; अथवा
  - ख. पाटन का जारी रहना तथा क्षति का बार-बार होना; अथवा
  - ग. पाटन और क्षति का बार बार होना।
- (ट) “अथवा” शब्द का प्रयोग सामान्य वैकल्पिक अर्थ में किया जाना चाहिए जो यह दर्शाता है कि उपर्युक्त स्थितियां पारस्परिक रूप से विशिष्ट हैं। यह कानून की निर्धारित स्थिति है कि “अथवा” शब्द का प्रयोग उसके सामान्य अर्थ में किया जाना है जब तक कि उसे वैकल्पिक रूप में पढ़ने से कोई अबोध या अभद्र अर्थ न आए। दिल्ली नगर निगम बनाम टेक चंद भाटिया (1980) आईएससीसी 158 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया जाता है।
- (ठ) इस प्रकार, यदि सतत पाटन एवं क्षति का मामला है तो संभवतः पाटन एवं क्षति बार-बार नहीं हो सकती क्योंकि क्षति के लिए अंतरनिहित रूप से उसे होने के लिए पाटन के अभाव की अपेक्षा होगी। चीन जन.गण. से “बेरियम कार्बोनेट” के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 15/27/2014 पर विश्वास किया जाता है जिसमें यह माना गया था कि पाटन एवं क्षति का जारी रहना यथा तथ्यतः पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से पाटन एवं क्षति की संभावना दर्शाता है और संभावना का



विश्लेषण ऐसे पाटन के कारण घरेलू उद्योग को सतत पाटन एवं सतत क्षति के कारण वर्तमान समीक्षा जांच में आवश्यक नहीं है।

- (ड) पाटनरोधी शुल्क अमरीकी डॉलर/किग्रा. में व्यक्त पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा (शुल्क का निर्धारित स्वरूप) के रूप में लगाया जाए।

## ट.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

89. वर्तमान जांच संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। नियमों के तहत प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखना आवश्यक है। इसमें इस जांच की भी आवश्यकता है कि क्या लगाये गए शुल्क से क्षति कारक पाटन को समाप्त करने का अपेक्षित प्रयोजन पूरा हो रहा है।
90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका से संबद्ध सामानों का सतत पाटन है जिससे घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटन बढ़ सकता है जो घरेलू उद्योग को चोट पहुंचा सकता है।

## ठ. निष्कर्ष

91. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष इस जांच परिणाम में रिकॉर्ड किए गए उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा परिणामस्वरूप क्षति के जारी रहने की स्थिति के उपर्युक्त विश्लेषण और पाटन एवं क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि :

- (i) संबद्ध देशों से संबंधित उत्पाद का निरंतर पाटन हो रहा है। जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है।
- (ii) पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है।
- (iii) पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद घरेलू उद्योग का वित्तीय निष्पादन खराब हुआ है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने उत्पादन, बिक्री, लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय जैसे आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में नकारात्मक वृद्धि दर्शायी है। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका से पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाते आ रहे हैं।
- (iv) यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका से विचाराधीन उत्पाद का पाटन जारी रहने/बढ़ने की संभावना है यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है।

## ड भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

92. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की परिपाटियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग को क्षति रूकेगी और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी तरह संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। उपभोक्ता फिर भी आपूर्ति के 2 अथवा अधिक स्रोत बनाए रख सकते हैं।
93. पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जोकि देश के सामान्य हित में है।

## ढ. सिफारिश

94. उपरोक्त निष्कर्ष निकालने के बाद, प्राधिकारी संबद्ध देशों (यानी यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका) से उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तु के सभी आयात पर पांच साल की अवधि के लिये एंटी-डंपिंग ड्यूटी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (8) में दर्शाया गया है, के निरंतर लगाव की सिफारिश करता है

## शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप शीर्ष	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2903 12	डिक्लोरोमेथीन (मिथाइलीन क्लोराइड)	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	मै. एकजो नोबल इंडस्ट्रीयल कैमिकल्स बी.बी., नीदरलैंड	मै. एकजो नोबल इंडस्ट्रीयल कैमिकल्स बी.बी., नीदरलैंड	0.32	किग्रा.	अम.डॉ.
2	2903 12	डिक्लोरोमेथीन (मिथाइलीन क्लोराइड)	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	क्र.सं.1 में संयोजन को छोड़कर कोई भी उत्पादक अथवा निर्यातक	क्र.सं.1 में संयोजन को छोड़कर कोई भी उत्पादक अथवा निर्यातक	0.36	किग्रा.	अम.डॉ.
3	2903 12	डिक्लोरोमेथीन (मिथाइलीन क्लोराइड)	संबद्ध देश को छोड़कर कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई भी	कोई भी	0.36	किग्रा.	अम.डॉ.
4	2903 12	डिक्लोरोमेथीन (मिथाइलीन क्लोराइड)	यूरोपीय संघ	कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	0.36	किग्रा.	अम.डॉ.
5	2903 12	डिक्लोरोमेथीन (मिथाइलीन क्लोराइड)	संयुक्त राज्य अमरीका	संयुक्त राज्य अमरीका	कोई भी	कोई भी	0.33	किग्रा.	अम.डॉ.
6	2903 12	डिक्लोरोमेथीन (मिथाइलीन क्लोराइड)	संबद्ध देश को छोड़कर कोई भी	संयुक्त राज्य अमरीका	कोई भी	कोई भी	0.33	किग्रा.	अम.डॉ.

			देश						
7	2903 12	डिक्लोरोमेथीन (मिथाइलीन क्लोराइड)	संयुक्त राज्य अमरीका	कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	0.33	किग्रा.	अम.डॉ.

#### ण. आगे की प्रक्रिया

95. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 22<sup>nd</sup> November, 2018

#### FINAL FINDINGS

**Subject: Sunset Review of anti-dumping investigation on the imports of “Methylene Chloride” originating in or exported from the European Union and the United States.**

#### A. BACKGROUND OF THE CASE

**F. No. 7/15/2018-DGAD.—** 1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

- Whereas having regard to the above Act and the Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") initiated an anti-dumping investigation against imports of Methylene Chloride originating in or exported from the European Union, the United States, and Korea RP vide Notification No.14/19/2012-DGAD on 04<sup>th</sup> April, 2013. The Preliminary Findings were notified on 06<sup>th</sup> September, 2013 and the provisional duties were imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 24/2013 – Cus (ADD) dated 21<sup>st</sup> October, 2013. The Authority had thereafter issued final findings on 2<sup>nd</sup> April, 2014 recommending the imposition of definitive anti-dumping duties on the subject imports. The definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from the subject countries were imposed by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 24/2014 – Cus (ADD) dated 21<sup>st</sup> May, 2014.

3. Whereas, in terms of the Act and the Rules, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition.
4. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
5. And whereas, M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. and M/s Chemplast Sanmar Ltd. (hereinafter also referred to as the "**Petitioners**" or "**Applicants**") filed an application before the Authority in accordance with the Act and the Rules alleging continuation of dumping of Methylene Chloride (hereinafter also referred to as the "**subject goods**") originating in or exported from the European Union and the United States, and the likelihood of continuation of dumping of the subject goods, originating in or exported from Korea RP, and consequent injury to the domestic industry. The Applicants have requested the Authority for review and continuation of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods from these countries.
6. And whereas, in view of the duly substantiated application filed in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules, and on finding that prima facie evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the United States of America (USA) and the European Union (EU) (hereinafter also referred to as the "**subject countries**"), injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exists to justify initiation of anti-dumping investigation; the Authority issued a public notice vide Notification No. F.No.7/15/2018-DGAD dated 03rd May, 2018 to examine whether the expiry of the anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
7. Since there were no imports of the subject goods from Korea RP in the POI and consequently no evidence of current dumping by the Korean producers, the sunset review investigation concerning imports originating or exported from Korea RP was not initiated.
8. The scope of the present review covers all aspects of the original investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

**B. GENERAL PROCEDURE**

9. The procedure described below has been followed with regard to this investigation, after issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigation by the Authority:
  - i. The Authority notified the Embassies/Missions of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the sunset review investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5.
  - ii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies/Missions of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the Applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
  - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies/Missions of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.

- iv. The Embassies/Missions of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- v. The Authority sent Exporter's Questionnaire to elicit relevant information from the following known producers/exporters in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

The European Union

- a) DOW Chemicals
- b) INEOS Chlor Limited
- c) Akzo Nobel Industrial Chemicals Ltd.
- d) Solvay SA - rue de Ransbeek
- e) Arkema SA
- f) M/s. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V

The United States

- a) Olin Corporation
- b) Occidental Chemical Corporation
- c) Dow Texas Operations 2301

- vi. However, no producer/exporter responded to questionnaire sent by the Authority.
- vii. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
  - a. Vardhaman Trading Corporation
  - b. Harsh Kumar & Company
  - c. Ralchem Limited
  - d. Morpean LABS
  - e. Surya Medicare Limited
  - f. Indsol Drugs Limited
  - g. Meghmani Organics Limited
  - h. United Phosphorus Limited
  - i. KDL Biotech Limited
  - j. Sun Pharmaceuticals Industries Limited
  - k. Rails India Limited
  - l. Alembic Limited
  - m. Hindustan Chemicals Industries
- viii. However, no importer of the subject goods responded to questionnaire sent by the Authority.
- ix. The Authority made available non-confidential version of the evidence and submissions presented by the interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- x. A request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- xi. The Non-Injurious Price (NIP) has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry, based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India. The optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods has been based on the information furnished by the domestic industry in

accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules.

- xii. The Authority held an oral hearing on 26<sup>th</sup> July, 2018 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6). The hearing was attended by the representatives of the domestic industry only, who presented their views orally and were subsequently advised to file written submissions of the same with the Authority.
- xiii. A disclosure statement, disclosing the essential facts of the investigation, was issued by the Authority on 12th November, 2018 inviting comments. No submissions have been made by any interested party apart from the domestic industry during the course of this investigation. Therefore, there were no submissions apart from the domestic industry that needed to be addressed by the Authority.
- xiv. Verification of the data of the domestic industry was carried out to the extent considered necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon by the Authority.
- xv. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review investigation is 1<sup>st</sup> January, 2017 to 31<sup>st</sup> December, 2017 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the years 2014-2015, 2015- 2016, 2016- 2017 and the POI.
- xvi. Information provided by the domestic industry on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, the domestic industry was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xvii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- xviii. ‘\*\*\*’ in this document represents information furnished to the Authority on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xix. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.66.07 = 1 US\$.

### C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

#### C.1 Views of the Domestic industry

10. The views of the domestic industry are as follows:

- i. The present investigation is a sunset review investigation. The product involved in the original investigation and in the present sunset review investigation is Methylene Chloride, also known as Dichloromethane or Methylene Dichloride (hereinafter also referred to as the "**subject goods**", or "**PUC**" or "**MDC**"). The product under consideration in the present sunset review investigation is the same as has been defined by the Authority in the original investigation.
- ii. Methylene Chloride is an organic compound with molecular formula CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>. It is a colourless liquid with sweetish ether-like odour and is used as a solvent predominantly. It is essentially non-flammable under most

conditions of use. However, it can burn if strongly heated. Methylene Chloride may decompose at high temperatures forming toxic gases. It is completely miscible with variety of solvents.

- iii. Methylene Chloride is a solvent and is used in the manufacturing of polycarbonate and phenolic resins, rayon yarn, pharmaceuticals, agro and fragrance chemicals. It is also used as an extractant for edible fats, cocoa, butter and essences.
- iv. The PUC in this investigation should remain the same as was defined in the course of the original investigation.
- v. Considering that the present application is for sunset review of existing anti-dumping duty and that there are no major developments since the previous investigations with regard to the PUC, the scope of the PUC is required to be kept the same as that in the original investigation.
- vi. There are no grades of the subject goods. However, it can be traded in loose or packed, thereby having direct effect on prices.
- vii. Methylene Chloride is classified under Chapter 29 (Organic Chemical) of the Customs Tariff Act, 1975, under customs subheading 29031200. The customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
- viii. There are two processes for production of Methylene Chloride – Methane route and Methanol route. The product produced through both the routes has essentially similar technical characteristics. Thus, the difference in production process does not result in a different product.

## **C.2 Views of other Interested Parties**

- 11. Since no interested party apart from the domestic industry has participated in this investigation, there are no submissions by other interested parties for the Authority to consider.

## **C.3 Examination by the Authority**

- 12. The product under consideration in this investigation is Methylene Chloride, also known as Dichloromethane or Methylene Dichloride. It is an organic compound with molecular formula  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ . It is a colourless liquid with sweetish ether-like odour and is used as a solvent, predominantly. It is essentially non-flammable under most conditions of use. However, it can burn if strongly heated. MDC may decompose at high temperatures forming toxic gases. It is completely miscible with a variety of solvents.
- 13. The subject goods are classified under Chapter 29 (Organic Chemical) of the Customs Tariff Act, 1975, under customs subheading 29031200. However, customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.
- 14. The present investigation being a sunset review investigation and anti-dumping duties, as recommended earlier by the Authority, being in force on the imports of the subject goods from the subject countries, the Authority considers that the scope of the subject goods in the present investigation remains the same as that in the original investigation.
- 15. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:

*"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*

16. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in the PUC exported from the subject countries and the product produced by the Indian industry. The goods produced by the domestic industry is comparable to the PUC in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
17. Thus, the Authority holds that the subject product produced by the applicant domestic industry is like article to the PUC exported from the subject countries, in accordance with the AD Rules.

#### **D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

##### **D.1 Submissions by the Domestic Industry**

18. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope and standing of the domestic industry:
  - i. The petition was jointly filed by Gujarat Fluorochemicals Ltd. and Chemplast Sanmar as the domestic producers of the PUC. There are three other producers of the subject goods in India, namely, TGV SRAAC Ltd. (formerly Sree Rayalaseema Alkalies and Allied Chemicals Ltd.), Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. and SRF Ltd. The Petition is supported by TGV SRAAC Ltd
  - ii. The Applicants account for 52.80% of the total domestic production and therefore can be termed to be holding a major proportion of the domestic production of the subject goods in India.
  - iii. The share of the Applicants along with the supporter accounts for 69.12% of the total Indian production.
  - iv. There are no imports of the PUC by the Applicants or any of their related parties during the POI, within the meaning of Rule 2(b) nor are they related to any of the importers or exporters for the subject countries. Therefore, the Applicants clearly satisfy the standing criteria and constitute domestic industry within the meaning of the Rules.

##### **D.2 Views of other Interested Parties**

19. Since no interested party apart from the domestic industry has participated in this investigation, there are no submissions by other interested parties for the Authority to consider.

##### **D.3 Examination by the Authority**

20. The application has been jointly filed by Gujarat Fluorochemicals Ltd. and Chemplast Sanmar and is supported by TGV SRAAC Ltd.
21. As per the information provided by the Applicants as part of their Petition, it can be seen that the Applicants constitute 52.80% of the total domestic production; and, after including the production of the supporter M/s TGV SRAAC Ltd, their collective share accounts for 69.12% of the total Indian production, as seen from the table below.



## Statement of Indian Production

S. No	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
<b>A.</b>	<b>Petitioner Companies</b>					
1.	Chemplast Sanmar Ltd.	MT	***	***	***	***
2.	Gujarat Fluorochemicals Ltd.	MT	***	***	***	***
	<i>Total of Applicants</i>	<i>MT</i>	<i>70,459</i>	<i>71,365</i>	<i>74,650</i>	<i>71344</i>
<b>B</b>	<b>Supporter</b>					
	TGV SRAAC Ltd.	MT	***	***	***	***
<b>C.</b>	<b>Other Indian Producers</b>	MT				
1.	Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd.	MT	***	***	***	***
2.	SRF Ltd.	MT	***	***	***	***
	<i>Total of Other Indian Producers</i>	<i>MT</i>	<i>39,271</i>	<i>39,636</i>	<i>41,724</i>	<i>41,733</i>
	<b>Total Indian Production</b>	<b>MT</b>	<b>1,09,730</b>	<b>1,11,000</b>	<b>1,33,572</b>	<b>1,35,125</b>
	<i>Share in Production</i>					
	Applicant Companies	%	64.21	64.29	55.89	52.80
	Supporters	%	-	-	***	***
	Other Domestic Producers	%	35.79	35.71	31.24	30.88
	<i>Total</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

22. Further, as per the information submitted by the Applicants, they are not found to have imported the subject goods during the POI, and they are also not found to be related to any exporter of the subject goods in the subject countries or any importer of the PUC in India within the meaning of Rule 2(b).

23. In view of the above and after due examination, the Authority holds that the Applicants satisfy the standing requirements and constitute domestic industry under Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

#### **E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY**

##### **E1. Examination by the Authority**

24. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to

all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).

25. There are no submissions made by the interested parties with regard to confidentiality.

**F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN**

**F.1 Determination of Normal Value for producers and exporters in the subject countries**

26. The provisions pertaining to normal value are given in Section 9A(1)(c) of the Act and Annexure - I to AD Rules. According to Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act, 1975, 'Normal Value' in relation to an article means:

*(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

27. None of the producers/exporters from the United States and the European Union have filed the response to questionnaire. In view of non-cooperation from producers /exporters from the subject countries, the Authority is not able to determine individual dumping margin and is constrained to proceed with the principles of best available information. The Authority determined normal value as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. Accordingly, Constructed Normal value has been determined as shown in the dumping margin table below.
28. The Authority has determined the Normal Value for the subject goods exported by all exporters in the subject countries by considering the optimum cost of production and after making additions for selling, general & administrative costs and providing reasonable profit.

**F.2 Determination of Export Price for producers and exporters in the subject countries**

29. The Authority has determined the export price for producers/exporters in the subject countries on the basis of the DGCI&S transaction -wise data. The export price has been adjusted on account of Freight, Marine Insurance, Bank Charges, Port Expenses to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for exports from subject countries is as shown in the dumping margin table below.

**F.3 Determination of dumping margin for producers and exporters in the subject countries**

30. Considering the normal value and export price as above, the dumping margin for all exporters of the subject goods from the subject countries is determined as below:

S.No	Particulars	UOM	United States	European Union
1a	Import volume Packed	MT	NIL	0.41
1b	Import volume Loose	MT	4,347	10,413
1	Total Imports	MT	4,347	10,414
2a	Constructed normal value- Packed	Rs./MT	***	***
2b	Constructed normal value Loose	Rs./MT	***	***
2	CNV- Wt. Avrg	Rs./MT	***	***
3a	NEP Packed	Rs./MT	***	***
3b	NEP Loose	Rs./MT	***	***
3	Net Export Price (Wt. Avrg.)	Rs./ MT	***	***
4a	Dumping Margin	Rs./ MT	***	***
4b	Dumping Margin	US\$/MT	***	***
4c	Dumping Margin	%	***	***
4d	Dumping Margin	Range	90-100	75-85

## G. INJURY AND CAUSAL LINK

### G.1 Views of the Domestic industry

31. The following are the injury related submissions made by the domestic industry during the course of the present investigation which are considered relevant by the Authority:
- Unlike original investigations, sunset reviews are prospective in nature, as they focus on the likelihood of the continuation or recurrence of dumping and injury, in case anti-dumping duties are removed.
  - With respect to injury determination, if the anti-dumping duty has had the desired effect, the condition of the domestic industry is expected to have improved during the period the anti-dumping duty was in force. Therefore, the assessment whether injury will continue, or recur, would entail a counter-factual analysis of the future events, based on projected levels of dumped imports, prices, and impact on domestic industry.
  - Imports from the EU increased in 2015-16, the year following the base year. The same decreased later till and including in the POI. However, the same remained substantial throughout the injury period.
  - Imports from the USA decreased throughout the injury period but so has the import price. However, the same remained substantial throughout the injury period.
  - The present decline in imports is due to anti-dumping duty in existence. Imports from the subject countries will, in all likelihood, regain the previous levels in the event of cessation of anti-dumping duty.
  - The share of subject imports in Indian demand has decreased throughout the injury period.

- vii. In the case of the EU and the USA, the landed price of imports is materially below the net sales realization throughout the injury period including the period of investigation.
  - viii. Price undercutting in case of imports of packed form decreased throughout the injury period and was negative in the POI owing to negligible volume of imports.
  - ix. The imports depressed the prices of domestic industry and prevented the price increases that would have occurred had it not been for dumping of the subject goods from the subject countries.
  - x. Production has increased slightly over the injury period but the same has decreased in the POI in comparison to the previous year.
  - xi. Domestic sales have increased over the injury period but the same have decreased in the POI as compared to the previous year.
  - xii. Capacity utilization in the POI is more or less at the same level as compared to the base year but the same decreased when compared to the previous year. The average industry norm is 95-100%.
  - xiii. The profitability, cash profits, PBIT, and return on investment have declined throughout the injury period and to a significant extent.
  - xiv. Market share of the domestic industry declined in the injury period including the POI.
  - xv. Inventories with the domestic industry have shown some increase over the injury period.
  - xvi. Employment level has been stable over injury period. Wages paid out have increased in the injury period.
  - xvii. Productivity per day has increased over the injury period. However, inspite of the same, the domestic industry is not able to earn the desired ROI and the same deteriorated over the injury period.
  - xviii. The domestic industry's ability to raise capital investments will be jeopardized in the event of cessation of anti-dumping duty.
  - xix. The injury margin is not only positive but also significant in case of USA and EU.
  - xx. The demand/apparent consumption of the subject goods has increased over the injury period. The demand in POI is 15% more than what it was in the base year.
32. The domestic industry made following submissions regarding the presence of causal link:
- i. Causal link has already been established in the original investigation.
  - ii. It is a settled position of law that causal link analysis is not mandatorily required to be done in a sunset review investigation. The WTO Appellate Body report in *US – OCTG* held that there is no requirement to establish the existence of a causal link between likely dumping and likely injury, as a matter of legal obligation, in a sunset review determination.
  - iii. Imports of the product from other countries are either attracting anti-dumping duty or are insignificant in volume or are at prices higher than the subject countries.
  - iv. There is no decline in demand and therefore possible decline in demand is not a factor of injury to the domestic industry.
  - v. There are no trade restrictive practices or technology issues which can be attributed to the cause of injury to the domestic industry.

- vi. Injury to domestic sales cannot be attributed to exports.
- vii. The productivity of the domestic industry has gone up over the injury investigation period. Therefore, productivity is not a cause of injury to the domestic industry.

## **G.2 Views of other Interested Parties**

33. Since no interested party apart from the domestic industry has participated in this investigation, there are no submissions by other interested parties for the Authority to consider.

## **G.3 Examination by the Authority**

34. The submissions made by the domestic industry during the course of investigation with regard to injury and causal link, and considered relevant by the Authority are examined and addressed as under:
35. The Authority has assessed injury by examining both volume effect and price effect. A determination of injury involves an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic industry.

### **G.2.1 Volume effect of dumped imports**

#### **a) Assessment of demand**

36. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

**Demand and Market Share**

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Sales of other Indian producers including supporter	MT	***	***	***	***
Imports from subject countries	MT	25,784	26,061	22,290	14,761
Imports from other countries attracting ADD	MT	27,295	69,146	40,847	39,463
Imports from Other Countries	MT	13,396	7,476	13,867	16,651
<b>Total Demand</b>	<b>MT</b>	<b>1,77,212</b>	<b>2,10,488</b>	<b>2,06,520</b>	<b>2,03,278</b>
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>119</i>	<i>117</i>	<i>115</i>

37. The Authority notes that the demand for the PUC increased significantly sin 2015-16 from 2014-15 but declined thereafter in 2016-17 and the POI.

**b) Import volumes and share of subject countries**

38. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject countries has been analysed as under:

**Imports and Market Share**

S.No	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1.a	Imports from EU	MT	12,936	18,997	15,482	10,414
1.b	Imports from USA	MT	12,848	7,064	6,808	4,347
1	<i>Imports from subject countries</i>	<i>MT</i>	<i>25,784</i>	<i>26,061</i>	<i>22,290</i>	<i>14,761</i>
2	Total Demand	MT	1,77,212	2,10,488	2,06,521	2,03,278
3	Total Indian Production	MT	1,09,730	1,11,000	1,33,572	1,35,124
Volume of imports from subject countries in relation to						
3.	Demand in India	%	14.55	12.39	10.79	7.26
4.	Production in India	%	23.50	14.47	16.69	10.92

39. From the above table, it can be seen that:

- The imports from the subject countries have declined over the injury period, except in 2016-17.
- The share of subject imports in relation to consumption in India has significantly decreased in 2015-16 from 2014-15. It increased thereafter in 2016-17 before declining to 7.26% in the POI.
- The share of subject imports in relation to production in India has decreased over the injury period, except in 2016-17. The share of subject imports in relation to production in India has fallen to 10.92% in the POI.

**G.3. 1. Import Price**

40. The import price from the subject countries has decreased over the injury period as would be seen from the table below. There is 21% decline in import price in the POI as compared to that in the base year. The import prices from subject countries are considerably lower than that from countries already attracting anti-dumping duty, and also from other countries.

**CIF Import Price**

S.N.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Import from Subject Countries	Rs./MT	34,229	28,303	25,310	27,208
(i)	EU	Rs./MT	36,645	28,247	25,720	27,288
(ii)	USA	Rs./MT	31,796	28,453	24,376	27,015
2	Other Countries attracting ADD	Rs./MT	41,270	35,248	27,036	28,638
3	Imports from rest of the countries.	Rs./MT	38,531	33,879	32,138	31,627

**G.3.2 Price effect of dumped imports**

41. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports when compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

**a) Price Undercutting**

42. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the PUC from the subject countries and the selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The price of the domestic industry was determined at the ex-factory level. The domestic prices and margin of undercutting is shown as per the table below:

**Price Undercutting**

S.No	Particulars	Unit	EU	USA	Subject Countries
1.	Landed price of imports without ADD	Rs./MT	29,690	29,393	29,603
2.	Net Sales Realisation of domestic industry in India	Rs./MT	***	***	***
3.a	Price undercutting without ADD	Rs./MT	***	***	***
3.b	Price undercutting without ADD	%	***	***	***
3.c	Price undercutting without ADD	Range	20-30	20-30	20-30
4.	Anti-dumping duty	Rs./MT	21,142	21,802	21,336
4.a	Price undercutting with ADD	Rs./MT	***	***	***
4.b	Price undercutting with ADD	%	***	***	***
4.c	Price undercutting with ADD	Range	(20-30)	(20-30)	(20-30)

43. Price undercutting by imports of subject goods (without including anti-dumping duty) from the EU and the USA is positive and substantial. When anti-dumping duty is included in the landed price of imports from the subject countries, the price undercutting becomes negative for both the EU and the USA.

**b) Price Underselling**

44. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from subject countries. For this purpose, the NIP determined for the domestic industry has been compared with the landed price of imports from subject countries. Comparison of the NIP of the domestic industry with weighted average landed price of imports shows as follows:

**Price Underselling**

S.No	Particulars	Unit	EU	USA	Subject Countries
1.	Landed price of imports without ADD	Rs./MT	29,690	29,393	29,603
2.	Non-Injurious Price	Rs./MT	***	***	***
3.a	Price underselling	Rs./MT	***	***	***
3.b	Price underselling	%	***	***	***
3.c	Price underselling	Range	40-50	40-50	40-50

45. It is noted from the above table that price underselling in respect of the import of subject goods from subject countries is positive and significant.

**c) Price suppression and depression effects of the dumped imports**

46. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority has considered the changes in the costs and prices over the injury period.

**Price Suppression/ Depression**

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Landed Price without ADD	Rs./MT	37,651	31,121	27,395	29,603
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>83</i>	<i>73</i>	<i>79</i>
Cost of sales per unit – domestic sales	Rs./MT	***	***	***	***



<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>96</i>	<i>101</i>	<i>112</i>
Selling price per unit – domestic sales	Rs./MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	<i>100</i>	<i>87</i>	<i>84</i>	<i>90</i>

47. From the above table, it can be seen that:

- The landed value of imports from the subject countries has declined in the injury period, having only increased in the POI.
- The cost of sales of the domestic industry has increased by 12% in the POI vis-à-vis the base year.
- Selling price of the domestic industry has declined by 10% in the POI vis-à-vis the base year.
- The effect of price depression and price suppression is thus visible.

#### **Conclusion on Volume and Price Effect**

48. While the volume of imports declined during this period, it nevertheless remained significant both in absolute terms and in relation to production and consumption. The import price has also declined over the injury period before increasing marginally in the POI. The effect of such dumped imports has been to depress the prices and prevent price increases which otherwise would have occurred.

#### **G.3.3 Examination of Economic Parameters relating to Domestic Industry**

49. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

50. It is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration; while some may show improvement. The Designated Authority considers all injury parameters and thereafter concludes whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments in the submissions.

51. Accordingly, various economic parameters of the domestic industry are analyzed herein below:

#### **a) Capacity, Production, Capacity Utilization and Domestic Sales**

52. The performance of the domestic industry with regard to production, capacity, capacity utilization, and domestic sales was as follows:

S.No.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1.	Capacity	MT	***	***	***	***
2.	Production	MT	***	***	***	***
3.	Capacity Utilisation	%	89	90	94	90
4.	Domestic Sales	MT	***	***	***	***

53. From the above table, it can be seen that:

- The domestic industry's capacity has remained constant throughout the injury investigation period.
- Production has increased throughout the injury period, except for the POI, when production declined as compared to that in the previous year.
- Capacity utilization of the domestic industry has been quite good during the injury analysis period.
- Domestic sales volume has increased throughout the injury period with marginal decline in the POI.

**b) Market Share**

54. The effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry has been examined as below:

**Market share in Demand**

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Share of domestic industry	%	40.36	32.97	35.76	36.13
Share of other producers including supporter	%	22.13	18.24	26.95	29.01
Share of domestic producers	%	62.49	51.21	62.71	65.14
Share of subject countries	%	14.55	12.39	10.79	7.26
Share of all other countries	%	22.96	36.41	26.5	27.6
Total	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

55. From the above table, it can be seen that:

- Market share of the domestic industry declined in 2015-16 and has thereafter been improving.
- Market share of other domestic producers declined in 2015-16 and has thereafter been improving.

iii. The market share of import from the subject countries has constantly declined during the injury period.

c) **Inventories**

56. The data relating to inventory of the subject goods is shown in the following table.

**Inventory**

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Inventory	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	138	264	136
Inventory, as no. of days of production	MT/day	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	138	264	136
Inventory, as no. of days of sales	MT/day	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	138	264	136

57. From the above table, it can be seen that:

- The average inventory increased throughout the injury period, except for a decline in the POI.
- The inventory per day in terms of both production and sales has followed the same trend.

d) **Profits, return on investment and cash flow**

58. The profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry has been analysed as follows:

**Profits, return on investment and cash flow**

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
PBIT – domestic sales	Rs. lacs	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	<i>Trend</i>	100	53	20	13
PBIT per unit – domestic sales	Rs. / MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	<i>Trend</i>	100	55	19	13
Cash Profits	Rs. lacs	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	<i>Trend</i>	100	24	20	55
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***

<i>Indexed</i>	<i>Trend</i>	100	66	22	17
----------------	--------------	-----	----	----	----

59. From the above table, it can be seen that:

- i. The profitability parameters of the domestic industry have declined over the injury period.
- ii. PBIT for domestic sales has declined substantially over the injury period. A similar trend can be seen for PBIT-per unit of domestic sales.
- iii. Cash profits made by the domestic industry have declined continuously in the injury period and the POI.
- iv. The domestic industry earned healthy ROCE in 2014-15. It however declined continuously in the injury period and the POI.

**e) Employment and Productivity**

60. The number of personnel employed by the Applicants and the position with regard to productivity is as follows:

**Employment and Productivity**

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
No of Employees	Nos	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	<i>Trend</i>	100	97	96	97
Productivity Per Day	MT/Day	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	<i>Trend</i>	100	101	106	101

61. From the above table, it can be seen that:

- i. The number of personnel employed by the domestic industry has remained more or less the same.
- ii. Productivity of the domestic industry has also witnessed marginal change during the injury period.

**f) Growth**

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Production volume	%	-	1.29	4.60	(4.43)
<i>Indexed</i>	<i>Trend</i>		100	358	(345)
Domestic sales volume	%	-	(2.96)	6.42	(0.58)
<i>Indexed</i>	<i>Trend</i>		(100)	217	(19)
Cost of sales per unit domestic sales	%	-	(4.09)	5.74	10.38

<i>Indexed</i>	<i>Trend</i>		(100)	140	254
Selling price per unit domestic sales	%	-	(13.00)	(4.69)	8.32
<i>Indexed</i>	<i>Trend</i>		(100)	(36)	64
PBIT per unit domestic sales	%	-	(41.83)	(59.33)	(36.91)
<i>Indexed</i>	<i>Trend</i>		(100)	(142)	(88)
PBIT per unit domestic sales	%	-	(44.93)	(64.65)	(33.43)
<i>Indexed</i>	<i>Trend</i>		(100)	(144)	(74)
ROCE per unit domestic sales	%	-	(33.92)	(66.04)	(23.05)
<i>Indexed</i>	<i>Trend</i>		(100)	(195)	(69)

62. The Authority notes that the growth of the domestic industry has been in the negative in the POI for all the aforesaid parameters.

**g) Ability to raise Capital Investment:**

63. There is no verifiable information either presented by the domestic industry or available on records on this issue. The Authority thus cannot make any conclusions regarding the impact of dumped imports on the domestic industry's ability to raise capital investments.

**H. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN**

64. The determined non-injurious price of the subject goods produced by the Domestic Industry has been compared with the landed value of the exports from subject countries for determination of injury margin during POI as under:-

**Injury Margin**

S.No	Particulars	UOM	United States	European Union
1a	Import volume Packed	MT	NIL	0.41
1b	Import volume Loose	MT	4,347.27	10,413.46
1	<b>Total Imports</b>	<b>MT</b>	4,347.27	10,413.87
2a	NIP Packed	US\$/MT	***	***
2b	NIP Loose	US\$/MT	***	***
2	<b>NIP- Wt. Avrg</b>	<b>US\$/MT</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
3a	Landed Value Packed	US\$/MT	***	***
3b	Landed Value Loose	US\$/MT	***	***
3	<b>Landed Value Avg</b>	<b>US\$/MT</b>	444.89	449.391

4a	<b>Injury Margin</b>	US\$/MT	***	***
4b	<b>Injury Margin</b>	%	***	***
4c	Injury Margin	Range	40-50	40-50

### **I. Conclusion on material Injury**

65. The Authority concludes that:

- a) Imports from the subject countries though declined over the injury period, but were nevertheless significant.
- b) The landed price of imports has declined over the injury period and has increased slightly in the POI.
- c) The imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry.
- d) The imports have depressed the prices of the domestic industry and have prevented the price increases that could otherwise have occurred.
- e) The profitability, cash profits, PBIT and return on investment have declined throughout the injury period and to a significant extent.
- f) Injury margin is not only positive but significant also.

66. Thus, the domestic injury has continued to suffer price injury despite anti-dumping duties being in force.

### **J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**

67. The Authority notes that this is a sunset review investigation and the focus of this investigation is to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury if the anti-dumping duties were to be allowed to expire.

#### **J.1 Submissions made by the Domestic Industry**

68. The domestic industry made following submissions in support of its claim of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

- i. The factors relevant to likelihood of dumping are relevant to the likelihood of injury as well in the present case.
- ii. Exports to the Indian market have been made at dumped prices. The dumping has continued from the USA and the EU.
- iii. The dumping and the injury margin in the current POI is positive and significant.
- iv. The price undercutting without prevailing antidumping duties is positive and significant.
- v. The current volume of imports itself is significant enough to establish the likelihood.
- vi. There is sufficient evidence that the volume of imports shall increase significantly in the event of revocation of anti-dumping duty.
- vii. Producers in the subject countries have significant freely-disposable production capacity which establishes that in the event of cessation of duties, exports to India will intensify.
- viii. The import prices are significantly below selling price of domestic industry. The consumers therefore

switched to imported products. In the event of cessation of anti-dumping duty, it will lead to significant increase in imports of the product.

- ix. The domestic industry is suffering price injury. Cessation of anti-dumping duty would atleast imply intensified injury to the domestic industry.
- x. In the view of huge spare capacities of the relevant exporters, and their aggressive exporting strategy, the domestic industry is destined to suffer greatly if the current anti-dumping duty protection is removed.
- xi. There is sufficient evidence that after cessation of anti-dumping duty, exporters of subject countries would export subject goods at dumped and injurious prices.

## **J. 2 Examination by Authority**

69. The Authority has examined the contentions of the domestic industry to examine likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury with specific reference to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules.

### **(a) Significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation**

70. The volume of subject imports in the current injury period has declined continuously since the imposition of the anti-dumping duty.

### **(b) Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports**

71. This parameter for ascertaining the threat of material injury/likelihood of recurrence of injury requires evaluation of existing surplus capacities and capacity addition, if any, to explore the possibility of diversion of disposable quantity to Indian market.
72. The domestic industry has collected information regarding demand, production and sales of the subject goods in the subject countries, from the Market Research Report on Methylene Chloride, as provided by P&S Market Research.
73. The Authority notes, on the basis of information submitted by the Applicants, that the aggregated capacities of all producers in the EU is 9,43,100 MT whereas the domestic demand for the subject goods in the EU is 2,90,100 MT. The exportable surplus in the EU has been estimated at 6,53,000 MT.
74. The Authority notes, on the basis of information submitted by the Applicants, that the aggregated capacities of all producers in the USA is 2,01,400 MT whereas the domestic demand for the subject goods in the USA is 1,19,500 MT. The exportable surplus in the USA has been estimated at 81,900 MT.

### **(c) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports**

75. The landed value of imports from the subject countries has declined in the injury period, having only marginally increased in the POI.

76. The cost of sales of the domestic industry has increased by 12% in the POI vis-à-vis the base year.
77. Selling price of the domestic industry has declined by 10% in the POI vis-à-vis the base year.
78. Imports from subject countries are thus causing depressing and suppressing effect on the prices of the domestic industry.

**(d) Inventories of the article being investigated**

79. The facts available on records do not contain any evidence regarding inventories of the PUC with the exporters in the EU and USA.

**K. OTHER KNOWN FACTORS & CAUSAL LINK**

**K.1 Examination by the Authority**

80. It was further examined whether other following parameters listed under the AD Rules could have contributed to injury to the domestic industry. It is noted as under:

**(a) Volume and prices of imports from third countries**

81. The prices of imports being higher, the imports of the subject goods from other countries could not have caused injury to the domestic industry.

**(b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.**

82. There has been increase in demand/apparent consumption of the subject goods over the injury period and hence contraction of demand cannot be a factor causing injury.

**(c) Developments in technology:**

83. Technology for production of the product concerned has not undergone any change.

**(d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

84. There is no trade restrictive practice, which could have affected the Domestic Industry.

**(e) Export performance of the domestic industry**

85. The injury analysis has been done by the Authority taking into consideration their domestic operations only. Therefore, performance in the export market has not affected the present injury analysis.

**(f) Productivity of the Domestic Industry**

86. The productivity of the domestic industry has witnessed only marginal change over the injury investigation period.

**K.2. Examination by the Authority**

**87 . Factors establishing Causal Link:**

- a) The imports from USA and EU have continued at dumped prices.
- b) The imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market. The domestic industry is also facing suppression & depression effect on its prices on account of dumped imports.
- c) The price depression/suppression has led to deterioration in profits, cash profits and ROI of the domestic industry.



- d) The producers in the subject countries have significant freely disposable production capacities. In the event of cessation of anti-dumping duty, the volume of dumped imports can witness increase.

## **L. POST DISCLOSURE COMMENTS**

### **L.1. Submissions by Domestic Industry**

**88.** The domestic industry, in its post disclosure submissions made following submissions. For the sake of brevity, comments made by the domestic industry, to the extent they are reiterations of the earlier submissions and already dealt with hereinabove, have not been repeated hereunder:

- a) Actual dumping margin has not been disclosed due to which an effective opportunity to make comments has been denied.
- b) The Authority may kindly specify in duty table that the subject goods should attract duty regardless of the customs classifications under which it is imported.
- c) None of the interested parties has participated in the present investigation. Thus, the Authority may consider the exporters non-cooperative and decide the matter as per Rule 6(8).
- d) While the Authority examined the likelihood of continuation of dumping and injury with specific reference to the parameters for threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules, it has neither acknowledged nor considered nor addressed the following submissions of the domestic industry:
  - (i) The dumping and injury margins determined in the original investigation and present investigation are positive and significant.
  - (ii) The domestic demand in EU is only 30.76% of the total capacities in EU. Further, the capacity in EU of the subject goods is 1185.42% of the total Indian capacity, 1321.92% of the Indian production and 1284.23% of the domestic sales of the domestic industry.
  - (iii) The additional production that can be achieved by the major producers in EU i.e. Akzo Nobel and INEOS is 36% of the Indian demand. There are other producers also in EU.
  - (iv) Similarly, the domestic demand in the USA is only 59% of the total capacities in the USA. Further, the capacity of the subject goods in USA is 253.15% of the total Indian capacity, 282.30% of the Indian production and 274.25% of the domestic sales of the domestic industry.
  - (v) The additional production that can be achieved by the major producers in USA is 29% of the Indian demand. There are other producers also in USA.
  - (vi) The producers and exporters in the USA and EU are export oriented and have exported to the world around 34% and 16% of their capacities respectively.
  - (vii) Akzo Noble, producer of subject goods in EU, has entered the design phase of a further expansion in Germany for the production of chloromethane.
  - (viii) While the use of methylene chloride in paint strippers is recently restricted in the EU, the same is going to happen in the USA as well. Thus, the weakening demand in EU and USA will lead to diversion of the subject goods to exports.
  - (ix) India is a lucrative market for the exporters. Asia Pacific is expected to be one of the fastest growing markets for Methylene Chloride due to increasing demand for solvents from various end-user industries. India and Pakistan accounted for second-largest market share for Methylene Chloride in Asia Pacific region. India is likely to be the fastest growing country for Methylene Chloride in this region.

- (x) Even if one of the conditions for likelihood is satisfied, duty cannot be allowed to expire. The same has been a consistent practice of the Authority.
- e) While the Authority has acknowledged the claim of the domestic industry regarding price difference in the landed and selling price, it has not addressed the issue. The analysis of this parameter is important in order to assess price attractiveness of Indian market. The price difference makes it evident that in the event of cessation of anti-dumping duty, the Indian market and prices would be too attractive to the foreign producers and is likely to motivate the foreign producers to increase their exports.
- f) Parameters of threat of material injury are not upper limit of parameters relevant to determination of likelihood and in case Designated Authority finds insufficient evidence of likelihood on the basis of threat parameters, Designated Authority is required to consider other parameters brought by the domestic industry
- g) In the Disclosure Statement issued, the Authority has examined the listed parameters under the Rules that could have contributed to injury to the domestic industry. The disclosed facts make it evident that none of the listed parameters have caused injury to the domestic industry. Nonetheless, the petitioners submit that the Authority has not acknowledged the following submissions made by the domestic industry, with respect to causal link:
- (i) It is a settled position of law that causal link analysis is not mandatorily required to be done in sunset review investigations. The same has been affirmed by the Appellate Body in Oil Country Tubular Goods from Mexico (WT/DS282/AB/R) dated 2 November 2005)
- (ii) The WTO Panel in US-DRAMS Case was also of the opinion that causal Link analysis is not a required factor in a sunset-review investigation.
- (iii) Imports of the product from other countries are either attracting anti-dumping duty or are insignificant in volume or are at prices higher than that from subject countries.
- (iv) The imports from USA and EU have continued at dumped prices and are available at prices lower than the domestic prices. Thus, if the anti-dumping duty is allowed to expire, the volume of dumped imports shall further intensify.
- (v) The imports would significantly undercut the prices of the domestic industry in case of cessation of duty. Resultantly, the domestic industry, which is already facing suppression and depression effect on its prices, would face further suppressing and depressing effect in case the ADD is not extended further.
- (vi) The price depression and suppression has led to deterioration in profits, cash profits and ROI of the domestic industry. Cessation of antidumping duty will result in further decline in profits and consequently return on capital employed and cash profits.
- (vii) The producers in the subject countries have significant freely disposable production capacities. In the event of cessation of anti-dumping duty, the volume of dumped imports would intensify.
- (viii) In case duty is ceased and consequently imports from the subject countries increase, the Domestic Industry would be forced to reduce the prices of the product concerned significantly and profitability would continue to deteriorate. The same would lead to further decline in cash flow and return on investment.
- Should the Domestic Industry choose to maintain its normal price levels, it is likely to lose its sales volume as consumers would increasingly switch over to the imports.
- h) The domestic industry requests the Authority to kindly consider the above while concluding the matter.
- i) The Rules clearly requires the establishment of any one of the following factors:
- a. Continuation of dumping and injury; or

- b. Continuation of dumping and recurrence of injury; or
- c. Recurrence of dumping and injury
- j) “Or” should be used in its ordinary disjunctive sense which indicates that the above situations are mutually exclusive. It is a settled position of law that the word “or” has to be used in its ordinary sense unless reading it as disjunctive would result in an unintelligible or absurd meaning. Reliance is place on Supreme Court Judgment in Municipal Corpn. Of Delhi v. Tek Chand Bhatia [1980) 1 SCC 158].
- k) Thus, if there is a case of continuing dumping and injury, then there cannot possibly be a recurrence of dumping and injury, since the latter would inherently require an absence of dumping to allow it to recur. Reliance is placed on Final Findings in Sunset Review of Anti-Dumping duties imposed on the imports of ‘Barium Carbonate’ from China PR, Notification No.15/27/2014 wherein it was held that the continuation of dumping and injury ipso facto indicates the likelihood of dumping and injury from the subject country in the event of cessation of the anti-dumping duty and that likelihood analysis is not a necessity in the present review investigation due to continued dumping and continued injury to the domestic industry on account of such dumping.
- l) Anti-dumping duty may be imposed as fixed quantum of anti-dumping duty (fixed form of duty), expressed in US\$/kg.

## **L.2. Examination by the Authority**

89. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from the subject countries. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of anti-dumping duty is warranted. This also requires examination whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.

90. The Authority notes that in the present investigation, there is continuous dumping of the subject goods from the EU and the USA, causing continued injury to the domestic industry. In view of the above, the Authority has reason to believe that in the event of cessation of anti-dumping duties, dumping may intensify from the subject countries causing injury to the domestic industry.

## **M. Conclusion**

91. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

- (i) There is continued dumping of the product concerned from the subject countries, causing injury to the domestic industry.
- (ii) Price undercutting without anti-dumping duty is positive and significant.
- (iii) Despite the anti-dumping duty in force, the financial performance of the Domestic Industry has deteriorated. During the POI, the domestic industry has shown negative growth in terms of the economic parameters such as production, sales, profitability and ROCE. The dumped imports from EU & USA continue to cause injury to the domestic industry.
- (iv) Dumping of the product under consideration from EU & USA is likely to continue/intensify should the current anti-dumping duty be revoked.

**N. Indian industry's interest and other issues**

92. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent injury to the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

93. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

**O. Recommendations**

94. Having concluded as above, the Authority recommends continued imposition of Anti-Dumping Duty as indicated in column (8) of the table below for a period of five years concerning all imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries ( i.e European Union and United State of America) .

**Duty Table**

Sl. No	Sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	European Union	European Union	M/s. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V, Netherlands	M/s. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V, Netherlands	0.32	Kg	US Dollar
2	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	European Union	European Union	Any producer or exporter other than combination at Serial Number 1	Any producer or exporter other than combination at Serial Number 1	0.36	kg	US Dollar
3	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	Any country other than subject countries	European Union	Any	Any	0.36	Kg	US Dollar
4	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	European Union	Any country	Any	Any	0.36	Kg	US Dollar

5	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	United States of America	United States of America	Any	Any	0.33	Kg	US Dollar
6	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	Any country other than subject countries	United States of America	Any	Any	0.33	Kg	US Dollar
7	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	United States of America	Any country	Any	Any	0.33	Kg	US Dollar

**P. Further Procedures**

95. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. and Director General.